राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड

संयोजक: बैंक ऑफ इण्डिया

पत्रांक संख्या : रा॰ स्त॰ बै॰ स॰ / 2022-23/96 दिनांक : 15.09.2022

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय / महोदया,

विषय:- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 80 वीं त्रैमासिक (जून 2022) समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

कृपया दिनांक 12.08.2022 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 80वी॰ त्रैमासिक बैठक का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त बैठक की कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही रिपोर्ट आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है,साथ ही हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की वेबसाइट (www.slbcjharkhand.org) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें दिनांक 30 सितम्बर 2022 तक प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इनका समावेशन किया जा सके।

भवदीय,

उप महाप्रबंधक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड

संगलन:- उपरोक्त अनुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक: 12.08.2022
स्थान– होटल रैडिसन ब्लू

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 80वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 80वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक 12.08.2022 को होटल रैडिसन ब्लू , राँची के **GBR** सभागार में आयोजित की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रांची क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक श्री संजीव सिन्हा ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार के सचिव, श्री अबूबक्कर सिद्दीकी,भा॰प्र॰ से॰,वित्त विभाग-झारखंड सरकार की विशेष सचिव, श्रीमती दीप्ती जयराज, एसएलबीसी झारखंड के संयोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री विक्रम केशरी मिश्र, नाबार्ड झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबन्धक श्री विनोद कुमार विष्ट ,झारखंड स्टेट लाइवलीहूड प्रमोशन सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सूरज कुमार, भा॰प्र॰ से॰ ,निदेशक,नगर निगम प्रशासन शहरी विकास एवं आवास निदेशालय,झारखंड सरकार से श्री अदित्य कुमार आनंद, भा॰प्र॰ से॰, एसएलबीसी के उप महाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार,भारतीय रिजर्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबन्धक श्री बिनोद मिश्रा उंपस्थित थे। इसके अतिरिक्त यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री ज्ञान रंजन सारंगी,अन्य सभी बैंकों के राज्य प्रमुख तथा सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं केंद्र/राज्य सरकार के अन्य विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक के क्रम मे सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न प्रमुख गणमान्य को सभा सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया,जिनकी प्रस्तुति निम्नतः है-

क) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक श्री बिक्रम केशरी मिश्र का सम्बोधन-

- श्री मिश्र ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं बैंकों के जून तिमाही के प्रदर्शन,अन्य नीतिगत मुद्दे एवं महत्वपूर्ण विषयो के संबंध मे सभा का ध्यान आकृष्ट किया।
- श्री मिश्र ने बताया कि पहली तिमाही के दौरान बैंको की जमा राशियों में 7.91% और ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 25.00% की वृद्धि देखी गयी। साथ ही पहली तिमाही के दौरान भी ऋण-जमा अनुपात में 5.86% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज हुई। श्री मिश्र ने पिछले वर्ष की तुलना में ऋण-जमा अनुपात में मामूली सुधार को सकारात्मक बताया, और इसे निरंतर जारी रखने हेतु समुचित प्रयास करने का अनुरोध किया। उन्होंने सभी बैंकों से राज्य की कृषि प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण में समग्र सुधार करने का आग्रह किया। **(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)**
- श्री मिश्र ने सभा के सदस्यों को प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण बकाया(Outstanding) में वर्ष-दर-वर्ष 21.18 % की वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र में 14.06 % की वृद्धि के संबंध मे अवगत कराया,वहीं कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण

मे 28.18% की वृद्धि एवं महिलाओं को दिये गए ऋण में भी 7.39% की वृद्धि के बारे मे भी सदन को बताया।

- उन्होंने सभी बैंकों को बधाई देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक ऋण योजना के तहत जून 2022 तक कुल उपलब्धि 35.31 फीसदी है, वहीं कृषि तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में उपलब्धि क्रमश: 14.76 और 55.21 फीसदी है।
- श्री मिश्र ने सदस्यों को संबोधित करते हुए बताया कि इस तिमाही के दौरान बैंकों ने राष्ट्रिय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 51,738 नए स्वयं सहायता समूहों मे क्रेडिट लिंकेज स्थापित किया एवं साथ ही इस तिमाही में सभी बैंको द्वारा राज्य के किसानो को 1.57 लाख किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए हैं।
- श्री मिश्र ने बताया कि हमारे राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि जून तिमाही के दौरान, समस्त बैंकों द्वारा 2.72 लाख अतिरिक्त मुद्रा ऋण हुए और साथ ही 32,370 पथ विक्रेताओं को PMSVANIDHI योजना के तहत ऋण सुविधा का विस्तार किया गया।
  (उपरोक्त विंदु सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)
- एसएलबीसी के महाप्रबंधक ने राज्य में कमजोर मानसून पर चिंता जाहिर की एवं इस संबंध मे "झारखंड फसल राहत योजना" को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया,साथ ही समस्त बैंकों के राज्य प्रमुखो से किसानों तक इस योजना की विस्तृत जानकारी का प्रसार करने का अनुरोध किया।
  (एक्शन-कृषि विभाग,राज्य सरकार)
- श्री मिश्र ने कहा कि वित्तीय समावेशन वर्तमान समय की आवश्यकता है और इसे वास्तविक अर्थों में सभी ग्रामीण जनता तक पहुँचाने मे बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। **(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)**
- श्री मिश्र ने जून, 2022 माह में जमशेदपुर में "वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता" विषय पर आयोजित विशेष एसएलबीसी मे अपेक्षीत मुद्दे विशेषतःमाननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड द्वारा की गयी परिचर्चा का ज़िक्र किया एवं इस वर्ष झारखंड राज्य मे 76 नई बैंक शाखाओ की स्थापना के संबंध मे विषय वस्तु पर की गई कार्रवाई से एसएलबीसी को अवगत कराने का आग्रह किया।
  (एक्शन-समस्त बैंक)
- श्री मिश्र ने अपने अंतिम वक्तव्य में सभी सदस्यो से आग्रह किया कि एसएलबीसी sub-committee में जो मुद्दे विस्तृत परिचर्चा किए जाते हैं उन विषयो पर सदस्य बैंकों को ध्यानपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है ताकि राज्य की बैंकिंग गतिविधियों एवं राज्य के समग्र विकास मे सहयोग कर सकें।
  (एक्शन-समस्त सदस्य गण/बैंक एवं एलडीएम)

ख) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के उपमहाप्रबंधक श्री सुबोध कुमार का सम्बोधन-

- श्री कुमार ने अपने सम्बोधन में वित्तीय सेवाएँ विभाग,भारत सरकार द्वारा झारखंड के दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से चिन्हित कुल 32 स्थानों पर Brick and Mortar शाखाएं खोलने के प्रस्ताव से सभी सदस्यो को अवगत कराया एवं इस विषय की मासिक प्रगति रिपोर्ट एसएलबीसी को प्रेषित करने का आग्रह किया। **(एक्शन-समस्त चिन्हित बैंक एवं संबन्धित एलडीएम)**
- श्री कुमार ने *"आज़ादी का अमृत महोत्सव"* के अंतर्गत विशेष केसीसी ड्राइव के दौरान बैंको के प्रदर्शन से सदस्यो को अवगत कराया। उन्होने सदन को बताया की इन अभियानों के दौरान 30 जून 2022 तक कुल

375.92 करोड़ रुपये के 7,733 आवेदन स्वीकृत किए गए एवं इनमे से 2019 आवदेनो में 98.61 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जा चुका है। (सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री कुमार ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर आयोजित एसएलबीसी उप-समिति द्वारा किए गए प्रमुख अह्वाहन के संबंध' मे सदस्यों को अवगत कराया एवं कहा कि आने वाले महीनों में खरीफ और पूर्व-रबी फसलों के लिए किसानों को फसल उपजाने, पशुपालन तथा मत्स्य पालन इत्यादि गतिविधियों हेतु ज्यादा से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने का आग्रह किया। (एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)
- श्री कुमार ने प्रत्येक ग्रामीण तथा अर्ध शहरी बैंक शाखा द्वारा एक गाव को गोद लेने के उदेश्य का ज़िक्र करते हुए वित्तीय समावेशन और ऋण संतृप्ति पर बैंकों को ध्यान केन्द्रित करने का आग्रह किया। इस संबंध में सभा को बताया गया कि पहले चरण के दौरान झारखंड के सभी जिलों में 1,638 गांवों को विभिन्न बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं यानी वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट संतृप्ति के तहत 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए चिन्हित किया गया है साथ ही उन्होने अन्य सदस्य जिन्होने अभी तक इस दिशा मे प्रगति नहीं की है उनसे अपील किया कि वे भी अपनी सभी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में उपरोक्त उद्देश्य हेतु कम से कम एक गांव को गोद लें तथा राज्य के गावों के विकास मे सहभागी बने।

  (एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)
- उन्होने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से राज्य मे बैंकों की गैर निष्पादित संपत्ति मे वसूली हेतु परस्पर सहभागिता की आवश्यकता बताई एवं SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत संपत्तियों के भौतिक कब्जे के लिए ज़िले मे लंबित मामले तथा Certificate Officer कार्यालय मे लंबित मामलों के निबटारे हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बतायी।

  (एक्शन-राज्य सरकार)
- अंत में श्री कुमार ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सभी सदस्य बैंको की तरफ से सदन को आश्वस्त किया कि राज्य के समग्र विकास में सभी संबंधित निकायों को राज्य स्तरीय बैंकेर्स समिति भरपूर समर्थन और सहयोग देने के लिए तत्पर है साथ ही भविष्य में भी अपनी प्रमाणिक भूमिका, नवऊर्जा तथा समर्पण के साथ प्रदान की जायेगी।

  (सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

ग) नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री बिनोद कुमार बिष्ट का सम्बोधन-

- मुख्य महाप्रबंधक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के मंच को सभी सदस्य बैंकों के लिए अति महत्वपूर्ण मंचों में से एक बताया तथा मंच के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। (सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)
- मुख्य महाप्रबंधक ने पिछले वर्ष की जून तिमाही की तुलना में राज्य के ऋण-जमा अनुपात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने पर सभी सदस्यों को बधायी दी। (सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)
- श्री बिष्ट ने सदस्यों को राज्य में व्याप्त सूखे की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने सदस्यों को यह भी बताया कि राज्य के एक तिहाई हिस्से में औसत से काफी कम बारिश हुई है, जो बैंकों, किसानों और राज्य सरकार के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है साथ ही उन्होने सदस्यों को कुछ अलग सोचने और करने का महत्वपूर्ण

अवसर भी बताया। श्री बिष्ट ने सदस्यों से कहा कि राज्य में कृषि और संबन्धित गतिविधियों में विकास बहुत अधिक नहीं है और सदस्यों को इस पर वृहत स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। **(एक्शन-राज्य सरकार)**

- श्री बिष्ट कि पिछली तिमाही की तुलना में 30 जून 2022 को विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के खातों की संख्या में आयी गिरावट पर चिंता ज़ाहिर की एवं सदस्य बैंकों से इसे आगे बढ़ाने तथा सितंबर 2022 तक प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र के तहत आबंटित लक्ष्य का कम से कम 40% लक्ष्य हासिल करने का आग्रह किया।
(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)
- मुख्य महाप्रबंधक ,नाबार्ड ने सदस्य बैंकों को व्यावसायिक अवसरों और बैंकों के लाभ के लिए विकासात्मक रणनीतियों के बारे में जानकारी दी तथा बैंको को farmer's producer organization (FPO)तथा उन्हे ऋण देने की आवश्यकता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य में अन्य कृषि क्षेत्र मे कम अवसर उपलब्ध हैं जिनमे एफपीओ वित्तपोषण हम सभी के लिए फायदेमंद होगा साथ ही राज्य में एफपीओ के गठन मे कई संगठन सहयोग कर रहे हैं। उन्होने बताया कि मौजूदा स्थिति मे एफपीओ को रु.25.00 लाख से रु.100.00 लाख तक के टर्म लोन अथवा कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओ की पूर्ति बैंक ऋण द्वारा की जा सकती है।
(एक्शन-समस्त बैंक एवं एलडीएम)
- श्री बिष्ट ने एफपीओ गठन, जेएलजी, एसएचजी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्र में कार्य कर रहे अग्रणी ज़िला प्रबन्धको के भूमिका की सराहना की, उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत FPO को लाभान्वित करने तथा जल्द से जल्द लाइसेंस प्रदान करने मे राज्य सरकार की भूमिका पर प्रकाश डाला।
(एक्शन-राज्य सरकार)
- उन्होंने सदन को आगे बताया कि FPO को ऋण सुविधा की गारंटी नाबार्ड की एजेंसी नबसंरक्षण द्वारा दी जाती है जो कुल ऋण राशि का लगभग 85% होता है। अतः बैंकों को इस वित्तीय वर्ष मे FPO को ज्यादा से ज्यादा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर विचार व्यक्त किया। **(एक्शन-समस्त बैंक)**
- नाबार्ड ने सदस्यों को जेएलजी के महत्व के बारे में भी सूचित किया और तिमाही के पहले दो महीनों में लगभग 5,000 जेएलजी के वित्तपोषण के लिए अध्यक्ष JRGB और ग्रामीण बैंक की पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही झारखंड राज्य सहकारी बैंक द्वारा अगले दो महीनों में 2,000 जेएलजी के वित्तपोषण के लक्ष्य के संबंध मे भी सभा को अवगत कराया। **(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**
- श्री बिष्ट ने सदस्यों को AIF के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक प्रमुख योजना है हालांकि यह कार्यक्रम राज्य में फलीभूत नहीं हो पा रहा है। उन्होने बताया कि इस योजना मे भारत सरकार द्वारा इंटरेस्ट सबवेंशन तथा क्रेडिट गारंटी की सुविधा भी दी जा रही है।राज्य के सभी बैंकों को इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुचाने का आग्रह किया।
(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)
- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम की महत्ता बतायी साथ ही नाबार्ड द्वारा कौशल कार्यक्रमों मे सहयोग के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने नाबार्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के बारे में बताया कि राज्य मे केवल 8% कौशल/प्रशिक्षित श्रमिक हैं उन्होने इन श्रमिकों को RSETI के माध्यम से प्रशिक्षित करने पर ज़ोर दिया । उन्होंने आश्वासन दिया कि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नाबार्ड RSETIs के साथ भविष्य मे भागीदारी करने को तैयार है।नाबार्ड ने वित्तीय संस्थानों से गैर-कृषि ऋण जैसे हैंडलूम, हस्तशिल्प आदि के तहत क्लस्टर वित्तपोषण के लिए भी आग्रह किया।
(एक्शन-समस्त RSETI Sponsored बैंक)

- श्री बिष्ट ने सदस्यों को बताया कि वित्तीय समावेशन और वित्तीय प्रौद्योगिकी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और इन क्षेत्रों के तहत पिछले दस वर्षों से लगातार कार्य किया जा रहा है लेकिन अभी भी इसमे काफी संभावनाए हैं। उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि नाबार्ड के पास वित्तीय समावेशन निधि के तहत विशेष निधि उपलब्ध है जिससे बैंक, ग्रामीण स्तर के कार्यक्रमों, वित्तीय साक्षरता, बीसी शुल्क की प्रतिपूर्ति इत्यादि के तहत योजना का लाभ उठा सकते हैं। **(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**
- मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने अपने सम्बोधन में नाबार्ड द्वारा उपलब्ध अनुदान सहायता की जानकारी दी जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थानों इत्यादि के स्तर पर सहयोग के अवसरों का पता लगाया जा सके।अंत में, नाबार्ड ने राज्य के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में सदस्य बैंकों के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। (सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

घ) भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक श्री संजीव सिन्हा का सम्बोधन

- श्री संजीव सिन्हा ने अपने भाषण को तीन श्रेणीयों मे विभाजित किया-
  - ✓ **RBI initiative on policy development:**

- श्री सिन्हा ने नीति विकास पर सदस्यों को सूचित किया एवं बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर दो चर्चा पत्र लाए गए हैं जिसे एसएलबीसी तथा सरकारी एजेंसीज के साथ साझा किया गया। इन पत्रों मे प्रथम पत्र वित्तीय प्रणाली पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर नीति कैसे तैयार की जाए एवं दूसरा डिजिटल लेंडिंग जिसमें वित्तीय संस्थानों द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं मोबाइल ऐप के द्वारा कर्ज देना शामिल है। इस संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक को मोबाइल ऐप और डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा कर्ज वितरण के दौरान अनियमितता संबंधी शिकायतों का ज़िक्र किया। श्री सिन्हा ने आरबीआई के चर्चा पत्रपर राज्य सरकार सहित अन्य सदस्यों से भी इनपुट प्रदान करने का अनुरोध किया है जिससे इस विषय पर नीतियां बनायी जा सके। (सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)
- श्री सिन्हा ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) का निर्माण किया है। उन्होंने विस्तार से बताया कि यह सूचकांक कुछ उप मापदंडों का गठन करता है जिसके तहत सूचकांक का निर्माण किया जाता है। श्री सिन्हा ने सहर्ष बताया कि यह सूचकांक मार्च, 2021 में 53.9 था जो बढ़कर मार्च, 2022 में 56.4 हो चुका है। (सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)
- श्री सिन्हा ने सदस्य बैंकों को बताया कि वित्तीय समावेशन न केवल लोगों के बैंकों से जुड़ने मे सहयोग कर रहा है बल्कि बैंकों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है वित्तीय समावेशन बैंकों मे ग्राहकों का आधार बढ़ा रहे हैं साथ ही बैंकों कों काफी कम लागत वाली जमा राशि भी प्रदान कर रहे हैं। उन्होने बताया कि सभी स्तरों पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने मे भारतीय रिजर्व बैंक एवं बैंकों द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं। महाप्रबंधक ने झारखंड के सुदूर गाँवो मे बैंकिंग आउटलेट प्रदान करने में Business Correspondents की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। (सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)
- अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डेबिट/क्रेडिट कार्ड धारकों की सुरक्षा देने के संबंध मे सभी सदस्यों को Tokenisation System से भी अवगत कराया। उन्होंने इस संबंध मे बताया कि भारतीय रिजर्व के इस पहल से बैंक कार्ड धारकों की सुरक्षा और अधिक सुदृढ होगी।उन्होंने सभा को बताया कि यह प्रक्रिया कार्ड धारकों द्वारा किए जा रहे डिजिटल ट्रांज़ैक्शन हेतु काफी महत्वपूर्ण है।उन्होने आगे जानकारी दी कि उपरोक्त प्रक्रिया के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 30 सितंबर, 2022 तक की समय सीमा बढ़ायी जा चुकी है। (सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

✓ State Level Development and Issues:

- श्री सिन्हा ने सदन को बताया कि ऋण-जमा अनुपात में तिमाही दर तिमाही वृद्धि 0.53% रही है। उन्होंने सदस्यों से एसएलबीसी की देख रेख में ऋण-जमा अनुपात में सुधार पर चर्चा करने को कहा,उन्होने बताया कि ऋण-जमा अनुपात के द्वारा राज्यों की प्रगति की तुलना की जाती है अतः ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित सुधार लाने हेतु एसएलबीसी के सभी सदस्यों को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता बतायी।

  (एक्शन-एसएलबीसी के सभी सदस्य)
- श्री सिन्हा ने एमएसएमई ऋण के तहत एसीपी में प्रस्तुत विभिन्न बैंकों के आंकड़ों मे विषमता पर नाराजगी जाहिर की,उन्होने बताया कि कुछ बैंकों ने एमएसएमई क्षेत्र मे एसीपी के लक्ष्य के विरुद्ध 97% उपलब्धि दर्शायी है वहीं कुछ बैंकों की उपलब्धि 10% से भी नीचे है। उन्होंने राज्य मे एमएसएमई क्रेडिट को बढ़ावा देने हेतु सदस्यों को अपनी ऋण प्रक्रिया/ प्रणाली/ रणनीति/कार्यप्रणाली पर गौर करने का अनुरोध किया जिसके माध्यम से राज्य मे एक समान एमएसएमई क्रेडिट को बढ़ावा दिया जा सके। **(एक्शन-एसएलबीसी के सभी सदस्य बैंक)**

- श्री सिन्हा ने जमशेदपुर में आयोजित विशेष एसएलबीसी के संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक श्री मिश्रा के भाषण का हवाला दिया, जिसमे बैंकों द्वारा राज्य मे लगभग 76 Brick and Mortar शाखाये खोलने के लिए प्रतिबद्धता ज़ाहिर की गयी। उन्होने एसएलबीसी को इस विषय पर बैंकों से विस्तृत जानकारी लेने को कहा ।

  (एक्शन-एसएलबीसी के सभी सदस्य बैंक)
- श्री सिन्हा ने आगे बताया कि आरबीआई केंद्रीय कार्यालय द्वारा संकलित बिज़नेस कोर्रेस्पोंडेस के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 1.45 लाख बीसी हैं, जिनमें से 0.54 लाख निष्क्रिय हैं तथा इन 1.45 लाख बीसी में 0.96 लाख बीसी यस बैंक के हैं और उनमे से 47% बिज़नेस कोर्रेस्पोंडेस निष्क्रिय अवस्था मे हैं। उन्होने यस बैंक द्वारा जून 2022 तिमाही मे एसएलबीसी को दिये गए आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि यस बैंक ने एसएलबीसी को राज्य मे शून्य बीसी होने की सूचना प्रदान की है। श्री सिन्हा ने यस बैंक के प्रतिनिधि को बीसी के आंकड़ों मे सुधार कर विस्तृत डीटेल (नाम/पते) सहित एसएलबीसी को सूचित करने को कहा साथ ही यह भी बताया कि भविष्य मे आरबीआई द्वारा येस बैंक के कुछ बीसी पॉइंट का onsite inspection भी किया जाएगा। वहीं फिनो पेमेंट बैंक द्वारा जून 2022 तिमाही मे दी गयी जानकारी तथा पिछली तिमाही के आंकड़ो मे उतार-चढ़ाव के विषय पर कहा कि संबन्धित बैंक को एसएलबीसी को विस्तृत जानकारी (नाम/पते) देनी चाहिए।

  (एक्शन-एसएलबीसी /येस बैंक/फिनो पेमेंट बैंक)
- श्री सिन्हा ने नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण विधि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बसी हुई भूमि के सीमांकन को सक्षम करने के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा शुरू किए गए SVAMITVA योजना का ज़िक्र किया। उन्होने बताया कि यह राष्ट्रीय महत्व की योजना है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय सुविधा का लाभ लेने के लिए अपनी ग्रामीण संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में

बैंको मे उपयोग करने की सुविधा बतायी। उन्होने बताया कि पूरे देश मे 20 जून 2022 तक लगभग 40,000 गांवों में 75 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इस संबंध में, उन्होने एसएलबीसी को राज्य में इस योजना मे हुई प्रगति पर चर्चा करने और इसे नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एसएलबीसी के एक एजेंडा आइटम के रूप में शामिल करने का आग्रह किया।

(एक्शन-एसएलबीसी)

✓ <u>Suggestion for State Level Bankers Committee</u>

- श्री सिन्हा ने एसएलबीसी के कार्यवृत्त में बैंकों द्वारा बताए गए कृत कार्यवाही के संबंध मे एसएलबीसी को इसकी समीक्षा करने तथा कृत कार्यवाही से संबन्धित कदमों के बारीकियों को शामिल करने का अनुरोध किया। उन्होंने कृत कार्यवाही को अति विशिष्ट बनाने का अनुरोध किया।

(एक्शन-एसएलबीसी)

- भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण पर श्री सिन्हा ने सदन को बताया कि यह राज्य मे लंबे समय से लंबित मामला है और एसएलबीसी को अपने कृत कार्यवाही में इस विषय की स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने एसएलबीसी से राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने का भी अनुरोध किया साथ ही भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के विषय को राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए भी काफी अहम बताया।

(एक्शन-एसएलबीसी/संबन्धित विभाग)

- श्री सिन्हा ने जिला स्तर पर आयजित होने वाले डीसीसी और डीएलआरसी बैठकों को अलग-अलग संचालित करने की आवश्यकता बतायी तथा एसएलबीसी को तिमाही मे आयोजित होने वाले डीसीसी/डीएलआरसी की बैठकों की विस्तृत विवरणी एसएलबीसी की पुस्तिका मे संलग्न करने का सुझाव दिया।

(एक्शन-एसएलबीसी)

- वार्षिक ऋण योजना को राज्य के विकास हेतु महत्वपूर्ण बताते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि एसएलबीसी द्वारा सौंपी गई भूमिका को बैंको को प्रभावी ढंग से निभाना चाहिए। उन्होने कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा एसीपी लक्ष्यों के तहत ऋण नहीं प्रदान करने या धीमी शुरुआत का ज़िक्र किया। साथ ही एसएलबीसी को 30 सितम्बर 2022 केउपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समग्र/विभिन्न क्षेत्रों के तहत कम एसीपी उपलब्धि वाले बैंकों के साथ बैठक कर बैंकों की बाधाओं को समझने तथा भविष्य की कार्यप्रणाली बनाने हेतु अनुरोध किया, साथ ही दिसंबर 2022 तिमाही के अंत में बैंकों के योगदान को उचित स्तर तक पहुचाने की सलाह दी।

(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)

- श्री सिन्हा ने अपने अंतिम वक्तव्य में पश्चिमी सिंहभूम जिले के मौजूदा ऋण-जमा अनुपात यथा 7.89% का ज़िक्र किया । उन्होंने एसएलबीसी को पश्चिमी सिंहभूम में ऋण-जमा अनुपात कम होने के कारणो को समझने तथा इस परिस्थिति से ज़िले को बाहर निकालने की दिशा मे कार्य योजना तैयार करने का आग्रह किया।

(एक्शन-एसएलबीसी/एलडीएम अग्रणी ज़िला प्रबन्धक वेस्ट सिंघभूम)

ङ) निर्देशक यूआईडीएआई, श्री नीरज कुमार का सम्बोधन

- श्री नीरज कुमार ने यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, रांची द्वारा तीन राज्यों (झारखण्ड,पश्चिम बंगाल,बिहार) मे दिये जा रहे सेवा के संबंध मे प्रकाश डाला। उन्होंने बैंक द्वारा समय-समय पर यूआईडीएआई के लक्ष्य प्राप्ति मे सहयोग करने की बात कही। **(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)**
- उन्होंने सदन को पूरे भारत वर्ष मे कुल 133 करोड़ आधार कार्ड निर्गत होने तथा 77 करोड़ बैंक खातों से आधार जुडने के संबंध मे जानकारी दी। उन्होंने झारखंड के संबंध मे बताया कि राज्य मे 95% आबादी के पास लगभग 3.70 करोड़ आधार कार्ड हैं साथ ही बैंकों को अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक करने पर अपनी भूमिका पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। **(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)**
- उन्होंने यूआईडीएआई की भौतिक और डिजिटल उपस्थिति के बारे में सदन को जानकारी दी। साथ ही बताया कि डिजिटल रूप से यूआईडीएआई mAADHAR ऐप के साथ मौजूद है और भौतिक रूप में राज्य के सभी 24 जिलों में आधार केंद्र मौजूद है साथ ही सरकार द्वारा राज्य के सभी 266 ब्लॉक में आधार केंद्र खोलने की योजना की भी जानकारी दी। **(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)**
- श्री कुमार ने बिज़नेस कोर्रेस्पोंडेंस को आधार कार्ड द्वारा बैंकिंग ट्रैंज़ैक्शन एवं खाते संबन्धित उपयोग विषय पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता बतायी तथा यूआईडीएआई द्वारा बैंको को प्रशिक्षण संबंधी सहयोग प्रदान किए जाने की जानकारी दी। **(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)**
- श्री कुमार ने सदस्यों को आधार समर्थित भुगतान प्रणाली के updation के बारे में बताया जिसमे बैंक के ग्राहकों को चेहरा पहचान माध्यम से भी भुगतान करने की व्यवस्था है। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि कोविड काल के दौरान राज्य में लगभग 1.70 लाख निवासी फेस रिकग्निशन तकनीक से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बैंको से अनुरोध किया कि वे अपने सिस्टम/डिवाइस को अपडेट करें ताकि face authentication माध्यम को बड़े पैमाने पर राज्य भर मे उपयोग मे लाया जा सके। **(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)**

ङ) सचिव कृषि विभाग श्री अबु बकर सिद्दीकी का सम्बोधन

- श्री सिद्दीकी ने एसएलबीसी के मंच को किसानों की ऋण आवश्यकताओ पर चर्चा करने हेतु काफी महत्वपूर्ण बताया साथ ही उन्होंने निम्न मुद्दों पर बैंको द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता बतायी:-
- सदस्य बैंकों से सभी किसानों को केसीसी को समर्थन प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने बैंकों द्वारा आवेदनों की भारी अस्वीकृति के बारे में अपनी नाराजगी बतायी और बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपूर्ण आवेदनों को पूर्ण करने मे किसानो का सहयोग करें व बिना किसी वैध कारणो के आवेदन अस्वीकृत ना करें। **(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)**
- श्री सिद्दीकी ने बैंको से पशुपालन और मत्स्य पालन हेतु किसानों को केसीसी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने और आवेदनों की स्वीकृति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध किया। **(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)**
- ऋण माफी योजना को श्री सिद्दीकी ने झारखंड सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बताया और शुरूवात मे बैंको द्वारा विभाग को लगभग 9 लाख मानक ऋणी किसानो का विवरण उपलब्ध कराने की जानकारी दी,

हालांकि इनमे से केवल 6 लाख किसानों का डेटा ऋण माफी पर अपलोड होने की जानकारी दी। उन्होंने बैंकों से इस विषय की समीक्षा करने तथा उनसे यह प्रमाण पत्र प्रदान करने का आग्रह किया कि बैंक द्वारा ऋण माफी योजना के तहत सभी किसान शामिल किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि अपलोड किए गए 6 लाख डेटा में से अब तक केवल 3.62 लाख किसानों को कवर किया गया है , शेष 2.38 लाख को ऋण माफी प्रदान करना शेष है। उन्होंने बैंकों से इन किसानों को योजना का लाभ दिलाने हेतु' जुटाने के लिए जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करने का अनुरोध किया।

(एक्शन-समस्त पात्र बैंक)

- सचिव कृषि ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बताया जहां किसानों को 6000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि भारत सरकार सभी PMKISAN लाभार्थियों के भूमि डेटा अपडेशन और ekyc के बारे में बहुत आवश्यक है, इसलिए वह बैंकों से ekyc के लिए सहयोग करने और किसानों के लिए शाखा स्तर पर लैंड डेटा और ekyc के अपडेशन के बारे में संदेश प्रदर्शित करने का आग्रह किया।

(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)

- श्री सिद्दीकी ने बैंकों द्वारा कृषि इन्फ्रा फंड वित्तपोषण पर अपनी नाराजगी दिखाई। उन्होंने विस्तार से बताया कि प्राप्त 195 आवेदनों में से 116 आवेदन केंद्रीय पीएमयू द्वारा स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 56 आवेदन बैंकों द्वारा खारिज कर दिए गए थे और जिनमें से 26 को "अपूर्ण दस्तावेज" होने के कारण खारिज कर दिया गया था। उन्होंने बैंकों से ऐसे आवेदनों पर पुनर्विचार करने और उनका समर्थन करने का अनुरोध किया।

(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)

- उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि इस वर्ष 3 करोड़ रुपये ब्याज सबवेंशन के लिए रखे गए हैं और सदस्यों से पात्र केसीसी खातों में जल्दी दावा करने का अनुरोध किया। (एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)
- उन्होंने बैंकरों से सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और गरीब किसानों का समर्थन करने का आग्रह किया ताकि वे अपने दम पर खड़े हो सकें और कृषि अर्थव्यवस्था विकसित हो सके। (एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)

छ) सीईओ जेएसएलपीएस श्री सूरज कुमार का सम्बोधन

- श्री सूरज कुमार ने समाज के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए जेएसएलपीएस की ओर से सभी बैंकरों को बधाई दी। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि राज्य ने क्रेडिट लिंकेज में 25% के लक्ष्य के मुकाबले 29% का लक्ष्य हासिल कर लिया है। (सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

  श्री कुमार ने सदस्यों को सूचित किया कि 16 अगस्त से 15 सितंबर तक एक अभियान प्रस्तावित है जिसमें बैंको को लक्ष्य का 50% प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंतिम तिमाही के दौरान ही बैंक मुख्य रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)

- श्री कुमार ने जेएसएलपीएस द्वारा जोहार परियोजना के तहत गठित 20 FPO के बारे में सदन को जानकारी दी, जो सालाना 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जेएसएलपीएस नाबार्ड के साथ FPO के गठन पर काम कर रहा है और बैंकों से उनका समर्थन करने का अनुरोध किया।

(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)

श्री कुमार ने बताया कि जेएसएलपीएस ने बैंकों को प्रशिक्षित सखी की बैंकवार तथा शाखावार सूची प्रदान की है और उन्होने इसे बीसी सखी के रूप में सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, क्योंकि ये सखी ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जा कर लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने में मदद करेंगी।
(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)

उन्होंने PMJJBY और PMSBY में लंबित दावों के निष्पादन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदस्य बैंकों से लंबित पड़े आवेदनों का जल्दी निपटारा करने का आग्रह किया।
(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)

- श्री कुमार ने सदस्य बैंकों से दोहरे प्रमाणीकरण के कार्यान्वयन के लिए कहा और सदन को सूचित किया कि जेएसपीएलएस डिजिटल लेनदेन के लिए एसएचजी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)

जेएसएलपी के सीईओ ने RSETIs के कामकाज के प्रति अपनी नाराजगी दिखाई। श्री कुमार ने सदन को बताया कि RSETIs को आवंटित लक्ष्य का केवल 13 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका है। इसके अलावा, उन्होंने निर्माणाधीन RSETIs भवनों को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया, ताकि आवासीय प्रशिक्षण किया जा सके साथ ही उन्होने अगली एसएलबीसी उप-समिति की बैठकों में RSETIs के प्रमुखों को आमंत्रित करने का अनुरोध किया।
(एक्शन-सभी संबन्धितबैंक)

ज) निदेशक, नगर निगम प्रशासन शहरी विकास एवं आवास निदेशालय श्री आदित्य कुमार आनंद

- श्री आनंद ने सदस्य बैंकों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह ऋण स्वीकृत करने पर और अधिक ध्यान देने का अनुरोध किया।
(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)
- श्री आनंद ने हाउसिंग लोन के तहत असंगठित क्षेत्र को लोन बढ़ाने के लिए सदन से अनुरोध किया। उन्होंने अन्य बैंकों से असंगठित क्षेत्र के लिए आवेदन स्वीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।
(एक्शन-समस्त सदस्य बैंक)

झ) विशेष सचिव वित्त विभाग, श्रीमती दीप्ति जयराज का सम्बोधन

- श्रीमती दीप्ति जयराज ने ऋण-जमा अनुपात और क्रेडिट लिंकेज में प्रगतिशील वृद्धि करने के लिए सभी बैंकों की सराहना की। उन्होंने आगे आने वाले समय मे भी अच्छे कार्यों को जारी रखने का अनुरोध किया।
(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)
- श्रीमती दीप्ति जयराज ने सभी सदस्यो को आश्वस्त किया की वित्त विभाग अन्य विभागों से समन्वय बनाने में पूरी तरह से सदस्यो के साथ काम करेगी ताकि राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जा सके।
(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)
- श्रीमती जयराज ने एसएलबीसी से एक ही स्थान पर सभी ब्याज सबवेंशन योजनावों के संबंध में डेटा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि बजट की समीक्षा के समय वित्त विभाग इस पर ध्यान केंद्रित कर सके।
(एक्शन-एसएलबीसी)
- श्रीमती जयराज ने सदन को सूचित किया कि विभाग ने SARFAESI के तहत काम किया है और जिला प्रशासन के साथ भी मामला उठाया है, हालांकि, 350 आवेदन अभी भी लंबित हैं जिन्हें जल्द ही प्रशासन के

साथ मिलकर निपटारा कर लिया जाएगा साथ ही साथ उन्होने सदस्यो को ये भी बताया की सरकार प्रायोजित योजना के अंतर्गत NPA कम करने को लेकर भी विभाग काम कर रहा है।

(सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

इस सम्बोधन के उपरांत एसएलबीसी के वरीय प्रबन्धक, श्री बिभव कुमार द्वारा एसएलबीसी बैठक के व्यवसायिक सत्र का संचालन किया गया, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा एजेंडावार विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों के प्रदर्शन पर चर्चा की गई।

अंत में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री ज्ञान रंजन सारंगी ने एसएलबीसी की 80वीं बैठक में शामिल सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। सभा का संचालन श्रीमती प्राची मिश्रा,अधिकारी, रा. स्त. बै. स द्वारा किया गया।

बि.के.मिश्र

(बिक्रम केशरी मिश्र)

महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI

80वीं एसएलबीसी बैठक, जून 2022

12 अगस्त होटल रेडिसन ब्लू, कडरू बाई पास रोड

क्रमांक	नाम	पद	विभाग	Contact No.
1	संजीव सिन्हा	महाप्रबंधक(प्रभारी अधिकारी)	भारतीय रिजर्व बैंक	
2	विनोद कुमार बिष्ट	मुख्य महाप्रबंधक	नाबार्ड	
3	श्रीमती दीप्ति जयराज	विशेष सचिव	वित्त मत्रांलय	
4	अबूबकर सिद्दीकी	सचिव	कृषि विभाग	
5	बिक्रम केशरी मिश्र	महाप्रबंधक	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
6	सूरज कुमार	सीईओ	जेएसएलपीएस	
7	आदित्य कुमार आनंद	निदेशक	शहरी विकास और आवास	
8	नीरज कुमार	निदेशक	यूआईडीएआई	
9	इंद्रजीत यादव	सहायक निदेशक	एमएसएमई	8126248984
10	जय निगम	डीजीएम	नाबार्ड	9425648274
11	बिनोद मिश्रा	एजीएम	भारतीय रिजर्व बैंक	9538323290
12	सुबोध कुमार	डीजीएम	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	7506256681
13	अमित विश्वकर्मा	प्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	8190042255
14	ए. शशांक सिन्हा	संयुक्त सचिव	वित्त विभाग	8987462074
15	एमडी आफताब उद्दीन	एजीएम	नाबार्ड	9546782666
16	प्रवीण कुमार सिंह	डीजीएम	भारतीय स्टेट बैंक	9004356910
17	हरि रमण	क्षेत्रीय प्रमुख	इंडियन ओवरसीज बैंक	8376959229
18	पीयूष भट्ट	अध्यक्ष	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	9492783000
19	ज्ञान रंजन सारंगी	फील्ड महाप्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9845416052
20	दीपक कुमार श्रीवास्तव	डीजीएम	पंजाब नेशनल बैंक	9491023304
21	सुनील कुमार	डीजीएम	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9264291876
22	रणवीर सिंह	डीजीएम	बैंक ऑफ इंडिया	
23	बिस्वजीत कुमार सिन्हा	एजीएम, एसएलबीसी	भारतीय स्टेट बैंक	7718825815
24	मनोज कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय प्रमुख	आईडीबीआई	7781021133
25	संजय कुमार खेमका	डीजीएम, रांची	बैंक ऑफ इंडिया	
26	एफ.आर. बुखारी	डीजीएम	इंडियन बैंक	9051658238
27	मनीष कुमार	एजीएम	बैंक ऑफ बड़ौदा	
28	बी.डी.कुजुरू	डीजीएम	केनरा बैंक	
29	रहमतुलाह हसन	निर्देशक	कृषि निदेशालय	
30	आशुतोष कुमार	सहायक निदेशक	कृषि निदेशालय	
31	विवेक मिश्रा	सहायक कृषि अभियंता	कृषि निदेशालय	
32	मुकेश कुमार सिन्हा	उप निदेशक	कृषि निदेशालय	
33	अजित कुमार	क्षेत्रीय प्रमुख	हुडको	9969293461
34	अमरेंद्र कुमार	एसएम (पी)	हुडको	9431815999
35	विनोद कुमार जायसवाल	उप प्रबंधक	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब रांची	9905082471
36	शैलेश प्रियदर्शी	सहायक निदेशक	यूडीडी	
37	लिपिका बनर्जी	एडीएफ (टेक.)	मत्स्य विकास	9431105224
38	रवींद्र कुमार महतो	वरिष्ठ कार्यकारी	सीएससी एसपीवी	79779990221
39	बीना कुमारी	वितीय बैंकिंग कार्यकारी	सीएससी एसपीवी	7870049012
40	उपेंद्र कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	सीएससी एसपीवी	9525107412
41	अमर दीप पांडेय	एओ	यूआईडीएआई	9811628343
42	जी भास्कर	एजीएम	बीएसएनएल	9431708882
43	शांतनु लाल	एजीएम	बीएसएनएल	9431104949
44	प्रेरणा जे होरो	प्रबंधक	सिडबी	7388777382
45	अरूप कुमार	प्रबंधक	सिडबी	9967067217
46	धीरज होरो	एसपीएम-एफआई	जेएसएलपीएस	8969170434
47	अनिल कुमार	एसएनओ, आरएसईटीआई	जेएसएलपीएस	9431901016
48	राजीव मल्होत्रा	सहायक निदेशक	केवीआईसी	9431169393
49	अनूप कुमार गुप्ता	सहायक निदेशक	केवीआईसी	8409672951
50	राजीव कुमार सिंह	वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी	आरईएस झारखंड	7004726652
51	शशि भूषण मिश्रा	एसडीआर झारखंड	नासेर	9330752100
52	चंद्र भूषण पांडेय	एससीआर झारखंड	रुडसेटी की राष्ट्रीय अकादमी	9073396646
53	पूनम किंडो	वरिष्ठ प्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	6287395612
54	राजीव रंजन	प्रबंधक	इंडियन बैंक	8617763005
55	संजय कुमार सिन्हा	मुख्य प्रबंधक	यूको बैंक	8016710116

56	प्रशांत कुमार	प्रबंधक	इंडियन ओवरसीज बैंक	7004759480
57	एच यदुनाथ बस्की	मुख्य प्रबंधक	पंजाब एंड सिंध बैंक	7508510730
58	हिमांशु शेखर	वरिष्ठ प्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9905774643
59	मनीष कुमारी	एवीपी	एचडीएफसी बैंक	9334612421
60	परविंदर सिंह	एवीपी	एचडीएफसी बैंक	9771413009
61	शब्बीर अख्तर	क्षेत्रीय प्रमुख बिक्री	आईसीआईसीआई बैंक	9771499046
62	राजेश कुमार	अभ	कर्नाटक बैंक	959934389
63	सुमित कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	ऐक्सिस बैंक	9693819579
64	राज कुमार कमल	क्षेत्रीय प्रमुख	इंडसइंड बैंक	9304143093
65	हिमांशु कुमार	क्लस्टर प्रमुख सेवा और संचालन	यस बैंक	7763803332
66	मनीष कुमार सिन्हा	शाखा प्रमुख	डीबीएस	9308457750
67	वी विजय कुमारी	प्रबंधक	करूर वैश्य बैंक	9505163871
68	अभय कुमार	क्लस्टर हेड	बंधन बैंक	9534130002
69	आर.के. सिन्हा	एजीएम	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	8210022097
70	मुकेश कुमार	प्रबंधक	झारखण्ड स्टेट कोपेरटिव बैंक	7766917111
71	कुणाल आनंद	क्लस्टर हेड	ईएसएफ़	8538910932
72	मनीष कुमार	क्षेत्रीय प्रमुख	उज्जीवन लघु वित्त बैंक	8789559190
73	मलय बोस	एवीपी और क्षेत्रीय ओपीएस प्रमुख	जन लघु वित्त बैंक	9513681903
74	अंशुल आनंदी	प्रतिनिधि	एयू लघु वित्त बैंक	8334937778
75	दिलशाद अली	प्रतिनिधि	फिनो पेमेंट बैंक	9308012968
76	बिराज डेका	मुख्य प्रबंधक	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक	9038224956
77	राजीव बनर्जी	एएसएम	पेटीएम	7631024490
78	बिपुल कुमार सिंह	बोकारो	द्वितीय पंक्ति अधिकारी	7909021904
79	देवब्रत शर्मा	चतरा	अग्रणी जिला प्रबंधक	8002738027
80	परमेश्वर मांझी	देवघर	अग्रणी जिला प्रबंधक	9955996404
81	राजेश कुमार सिन्हा	धनबाद	अग्रणी जिला प्रबंधक	8406002014
82	प्रवीण कुमार	दुमका	अग्रणी जिला प्रबंधक	9903491709
83	संतोष कुमार	पूर्वी सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	7260814454
84	इंदु भूषण लाल	गढ़वा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934363709
85	नीतीश कुमार	गिरिडीह	अग्रणी जिला प्रबंधक	7903761115
86	धर्मेश पांडेय	गोड्डा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7383400449
87	मनीषा कुमारी	गुमला	द्वितीय पंक्ति अधिकारी	8709568277
88	सुधाकर पांडेय	हजारीबाग	अग्रणी जिला प्रबंधक	9407585820
89	राम कृपाल बैठा	जामताड़ा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9341529204
90	बिनय कुजुरू	खूंटी	अग्रणी जिला प्रबंधक	8340514511
91	महेश प्रसाद	कोडरमा	अग्रणी जिला प्रबंधक	8051071834
92	शांति प्रसाद टोप्पो	लातेहारो	अग्रणी जिला प्रबंधक	7781011677
93	रवींद्र प्रसाद	लोहरदगा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9931108187
94	मनोज कुमार	पाकुर	अग्रणी जिला प्रबंधक	7889213363
95	अनुकरण तिर्की	पलामू	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934363710
96	संजीव कुमार	रामगढ़	अग्रणी जिला प्रबंधक	8709551260
97	श्रीकांत	रांची	अग्रणी जिला प्रबंधक	9798967181
98	सुधीर कुमार	साहिबगंज	अग्रणी जिला प्रबंधक	9771438409
99	बीरेंद्र केआर शीट	सराईकेला-खरसवान	अग्रणी जिला प्रबंधक	9572024420
100	संजीव कुमार चौधरी	सिमडेगा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7903780946
101	लक्ष्मी नारायण लगुरी	पश्चिम सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	8210786477